

प्रष्ठक.

मनोज चन्दन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

प्रमुख वन संस्कार,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2

देहरादून दिनांक 31 अक्टूबर, 2013

विषय:- वन विभाग के अनुदान सं0-27 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 के राज्य सेक्टर के आयोजनागत पक्ष की योजना “जंगली जानवर द्वारा सरकारी कर्मचारियों या जनता को जान-माल नुकसान पर क्षतिपूर्ति” में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर प्रमुख वन संस्कार, नियोजन एवं वित्तीय प्रधन्यन, उत्तराखण्ड के प0सं0 नि-609/3-5(जंगली जानवर मुआवजा) दि0-28 सितम्बर 2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वन विभाग के अनुदान सं0-27 के अन्तर्गत “जंगली जानवर द्वारा सरकारी कर्मचारियों या जनता को जान-माल नुकसान पर क्षतिपूर्ति” योजना में चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रथम अनुपूरक अनुदान सहित प्राविधानित आय-व्ययक रु 1,00,00,000/- (रु एक करोड़ मात्र) के सापेक्ष शासनादेश सं0-3304/X-2-2013-12(30)/2012 दि0-31 जुलाई, 2013 द्वारा अवमुक्त धनराशि रु 70,00,000/- (रु सतत लाख मात्र) के पश्चात् अवशेष कुल धनराशि रु 30,00,000/- (रु तीस लाख मात्र) व्यय किये जाने के लिए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं :-

1. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण निरामावली, 2012 द्वारा प्राविधानित सुनिश्चित व्यवस्थानुसार की जायेगी।
2. उक्त स्वीकृत व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाये और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नवे कार्यों के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय तथा विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-284/XXVII(1)/2013 दि0 30 मार्च, 2013 एवं शासनादेश सं0-413/XX VII(1)/2013 दि0 10 जून, 2013 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति/यथा स्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाय। किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनेजमेंट), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्योरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुनिश्चित नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगंतन का संक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण एवं तदोपरान्त वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जायेगा।
3. बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय। धनराशि का आहरण एवं व्यय अनुमोदित परिव्यय के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा। साथ ही पूर्व अवमुक्त धनराशियों के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति एवं व्ययोंगति प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जायेगा इसके अतिरिक्त योजना की प्रगति तथा उद्देश्यों की पूर्ति संतोषजनक होने पर ही धनराशि आहरित एवं व्यय की जायेगी।
4. आपके निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि आहरण-वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय, जिससे की फौल्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की विधित उत्पन्न न हो।
5. आहरण-वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण निर्धारित बी0एम0-प्रपत्र पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा।
6. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय को फैजिंग (त्रैमास के आधार पर) प्रशासनिक विभाग एवं वित विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा, जिससे की राज्य स्तर पर कैश-फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।
7. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि मजदूरी तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिये भुगतान मदों के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या सम्बन्धित इकाई में समक्ष स्तर के स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमा अन्तर्गत अथवा वित विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के अन्तर्गत ही रहेगी।

8. मानक मदों के आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-ब-06/X-2-2010-12(11)/2009 दि0 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
10. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का आवंटन पत्र कम्प्यूटर के माध्यम से जनरेट किया गया है एवं इसका Allotment Id S1310270511 है। आप भी अपने स्तर से अधिनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों को कम्प्यूटर के माध्यम से online बजट आवंटन करना सुनिश्चित करेंगे।
11. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यों की सूचना यथावश्यकतानुसार सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-1638/XXX-1-12(25)2011, दि0 8 दिसम्बर, 2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वेबसाइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जायेगी और उन्हें समय-समय पर अध्यावधिक किया जायेगा।
12. आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा।

2- उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या-27 के लेखा शीर्षक 2406-वानिकी तथा व्यय जीवन 01-वानिकी 800-वन्य व्यय 09 जंगली जानवर द्वारा सरकारी कर्मचारियों या जनता को जान-माल नुकसान पर क्षतिपूर्ति मानक मद 20-सहयक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता के नामे डाला जायेगा। इस प्रयोजन हेतु Online Budget Allotment की हार्ड कॉपी भी संलग्न की जा रही है।

3- उक्त आदेश वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-284/XXVII(1)/2013 दि0-30 मार्च, 2013 एवम् शासनादेश सं0-413/XXVII(1)/2013 दि0-10 जून, 2013 द्वारा दिये गये निर्देशों के आलोक भें निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)

अपर सचिव

संख्या- ५१२२
(1)/X-2-2013, तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार(ए एण्ड ई), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिलिंग, सहानपुर रोड, माजरा, देहरादून।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता एवं कानून प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
11. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

(मनोज चन्द्रन)

अपर सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20132014

Secretary, Forest (S016)

आवंटन पत्र संख्या - x-2-2013-12(30)/2006

अनुदान संख्या - 027

अलोटमेंट आई डी - S1310270511

HOD Name - Principal Chief Conservator of Forest (4260)

आवंटन पत्र दिनांक - 30-Oct-2013

1: लेखा शीर्षक	2406 - वानिकी तथा अन्य जीवन	01 - वानिकी
	800 - अन्य व्यय	09 - जंगली जानवर द्वारा सरकारी कर्मचारियों या जनता के
	00 - जंगली जानवर द्वारा सरकारी कर्मचारियों या जनता के	

Plan Voted			
मानक भद्र का नाम	पर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - प्रहार्यक अनुदान/अंशदान/राज	7000000	3000000	10000000
	7000000	3000000	10000000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 3000000